RNI No.: UPHIN/25/A1698

NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 090
दि. 29.07.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने दिव्या देशमुख को फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025 बनने पर बधाई दी

पीएम मोदी ने दिव्या देशमुख को फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025 बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा, "कोनेरू हम्पी ने भी चैंपियनशिप के दौरान जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासोंके लिए शुभकामनाएं।" पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया: दो उत्कृष्ट भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का एक ऐतिहासिक फाइनल! युवा दिव्या देशमुख के 2025 में फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर गर्व है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई, जो कई युवाओं को प्रेरित करेगी।

'वेंस ने कहा पाक हमले की तैयारी कर रहा, पीएम मोदी बोले- मुंहतोड़ जवाब देंगे...', संसद में जयशंकर ने बताई 9 मई की पूरी कहानी

(जीएनएस)।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि भारत और अमेरिका के बीच पाकिस्तान को लेकर किसी बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर पाकिस्तान द्वारा हमले की चेतावनी दी थी.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा में विस्तार से बताया कि भारत-पाकिस्तान टकराव के दौरान चलाए गए 'ऑपरेशन' सिंदूर के दौरान क्या-क्या हुआ था. साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने व्यापार के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाने की बात कही थी.

जयशंकर ने बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुआ.

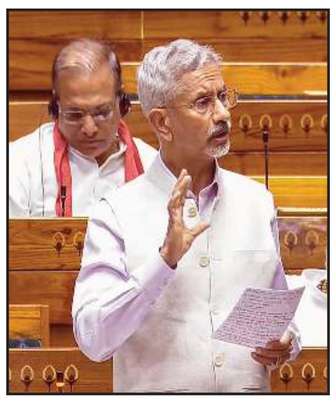

उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था. इस दौरान जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी कर रहे है. जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत उससे भी ज्यादा जोरदार जवाब देगा.

जयशंकर ने कहा कि 9 और 10 मई को पाकिस्तान की ओर से किए गए कई हमलों को भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया.

उन्होंने यह भी बताया कि 10 मई को कई देशों ने भारत से संपर्क किया और जानकारी दी कि पाकिस्तान युद्धविराम (सीजफायर) के लिए तैयार है. इस पर भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अगर युद्धविराम की बात करना चाहता है तो वह केवल सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) के माध्यम से ही बात करे.

विदेश मंत्री जयशंकर संसद के मानसून सत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जवाब देते हुए अमेरिका के साथ हुई बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं था, तो विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष अपने ही विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं करते और दूसरे देश पर भरोसा कर लेते हैं. मुझे आपत्ति है कि उन्हें भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है. मैं जानता हूं कि उनके दल में 'विदेश' शब्द का कितना महत्त्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी पार्टी की हर बात संसद पर थोपें. यही वजह है कि वे उस तरफ बैठे हैं और अगले 20 साल तक वहीं बैठे रहेंगे.

रक्षा मंत्रालय तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में परीक्षण सुविधा स्थापित करेगा

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 28 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में रक्षा परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना (डीटीआईएस) के अंतर्गत तिरुचिरापल्ली में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में, रक्षा मंत्रालय और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

डीटीआईएस 75 प्रतिशत तक सरकारी वित्त पोषण 'अनुदान सहायता' के रूप में प्रदान करता है। शेष 25 प्रतिशत विशेष प्रयोजन उपाय (एसपीवी) द्वारा वित्त पोषित किया

जाता है। इसमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य/केन्द्र सरकारें शामिल होती हैं।

यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र परीक्षण सुविधा के लिए, एक निजी संस्था, माइक्रो लैब्स, प्रमुख एसपीवी सदस्य है। एसपीवी संघ के अन्य सदस्य तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और वैधेश्वरन इंडस्ट्रीज हैं। परियोजना के पूरा होने पर, यह सरकारी और निजी दोनों उद्योगों को उन्नत परीक्षण उपकरण और सेवाएं प्रदान करेगा। इससे रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, निजी उद्योग और केंद्र/राज्य सरकार के सहयोग से अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने हेतु डीटीआईएस का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उत्पादन के माध्यम से और सैन्य उपकरणों के आयात को कम करके आत्मनिर्भरता

सीएम योगी बोले: बैठक का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं की समीक्षा नहीं, प्राथमिकता के आधार पर विकास सुनिश्चित करना है

वाराणसी। (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में वाराणसी और आजमगढ़ के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से उनके विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों, जन अपेक्षाओं और विकासपरक कार्यों की प्राथमिकताओं के विषय में एक-एक कर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा, बैठक का उद्देश्य मात्र योजनाओं की समीक्षा ही नहीं बल्कि जनोपयोगी, दूरवर्ती क्षेत्र का प्राथमिकता के आधार पर विकास सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, नगर विकास और पर्यटन से संबंधित जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की विधानसभावार चर्चा की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जनोपयोगी एवं विकासपरक कार्यों के प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करें। उनका अविलंब एस्टीमेट तैयार कर अन्य औपचारिकताएं पूरी कराते हुए तत्काल कार्य शुरू किया जाए। जिन सड़कों, पुलों, छोटे पुलों की ज्यादा जरूरत हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। औद्योगिक क्षेत्रों, ब्लॉक मुख्यालयों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को प्राथमिकता पर लिया जाए। इसके बाद चरणवार अन्य कार्य कराए जाएं।

मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के कार्यों में भी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में दोनों मंडलों में पर्यटन विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की मंशा हर जनोपयोगी एवं विकासपरक योजनाओं को मूर्त रूप देना है। इसके लिए संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रस्तावित कार्यों को समयसीमा में गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने वाराणसी में निमार्णाधीन पर्यटन सुविधा केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज वाराणसी में दुगार्कुण्ड स्थित धर्म संघ शिक्षामण्डल में पर्यटन विभाग द्वारा 05 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से निमार्णाधीन पर्यटन सुविधा केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए।

पर्यटन सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य अक्टूबर, 2025 में पूरा कराए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी निरीक्षण के दौरान ने धर्म संघ के मन्दिर में दर्शन-पूजन भी किया तथा गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। इससे पूर्व, धर्म संघ के महंत ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की बेहतर खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कदम

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई, 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा राशि मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में हासिल किया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्ज्वला 2.0 को अगस्त 2021 में 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। यह लक्ष्य भी जनवरी 2022 में हासिल किया गया। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का फैसला किया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी जिसे जुलाई 2024 तक हासिल कर लिया गया।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की निगरानी पीपीएसी की खपत रिपोर्ट, कॉमन एलपीजी डेटा प्लेटफॉर्म (सीएलडीपी) और ओएमसी के साथ बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि भोजन की आदतें, परिवार का आकार, खाना बनाने की आदतें, परंपरा, स्वाद, पसंद, कीमत, वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता आदि। योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और एलपीजी उपयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए, ओएमसी नियमित रूप से ग्राहकों के लिए एलपीजी पंचायत आयोजित करती हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की बेहतर खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें सब्सिडी राशि से ऋण वसूली को स्थगित करना, अग्रिम नकद खर्च को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम की जगह 5 किलोग्राम सिलेंडर का विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बोतल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए मनाने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन व जागरूकता अभियान शामिल हैं।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक) के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी शुरू की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी के बाद, भारत सरकार दिल्ली में 553 रुपये प्रति सिलेंडर की प्रभावी कीमत पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर 4.47 (वित्त वर्ष 2024-25) हो गई है।

पीएमयूवाई कनेक्शनों की निष्क्रियता का आकलन उन उपभोक्ताओं के माध्यम से किया जा सकता है जिन्होंने कनेक्शन लगवाने के बाद कोई रिफि ल नहीं लिया है।

01.07.2025 तक, लगभग 1.3 प्रतिशत पीएमयूवाई उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन लगवाने के बाद से कोई रिफि ल नहीं लिया है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चला है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाली महिलाओं और परिवारों के जीवन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ प्रमुख लाभों का संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है:

(६) पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप खाना बनाने के पारंपरिक तरीकों में बदलाव आया है जिनमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेषों को जलाना शामिल है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर का वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है, खासकर महिलाओं और बच्चों में जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएं के संपर्क में अधिक आते हैं।

(६) ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर दूरदराज के इलाकों में, परिवार अक्सर अपना काफी समय और ऊर्जा पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जुटाने में लगाते हैं। एलपीजी ने गरीब परिवारों की महिलाओं की मेहनत और खाना पकाने में लगने वाले समय को कम किया है।

शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एनईपी 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का शुभारंभ करेंगे

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई, 2025 को भारत मंडपम परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, 2025 का आयोजन कर रहा है । दिन भर चलने वाले इस विचार-विमर्श का उद्घाटन शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला अखिल भारतीय शिक्षा समागम (एबीएसएस) 2025, शिक्षाविदों, नीति निमार्ताओं, शिक्षकों, उद्योग जगत के दिग्गजों और सरकारी प्रतिनिधियों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर वे एनईपी 2020 के तहत हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा करके आगे का रास्ता निर्धारित करेंगे। एबीएसएस 2025 के दौरान होने वाले विचार-विमर्श में शिक्षा को अधिक सुलभ, व्यावहारिक, कौशल-उन्मुख और रोजगार के अवसरों के साथ समेकित रूप से एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र एक सशक्त व ै श्‍ व ि क अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हों। चर्चा में विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा को 2030 तक शत-प्रतिशत जीईआर प्राप्त करने हेतु पुनर्परिभाषित करने, भारतीय भाषाओं, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) को मुख्यधारा में लाने और सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु समावेशिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्श्. एबीएसएस 2025: एनईपी 2020 की 5वीं वर्षगांठ

अपनी शुरूआत के बाद से पिछले पांच वर्षों में, एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा में भारत के शिक्षा परिदृश्य में क्रांति ला दी है, और ऐसी परिवर्तनकारी नीतियां पेश की हैं जो अनुकूलन, समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। 170 विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से शैक्षणिक, कौशल-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा में निर्बाध ऋण वितरण को सक्षम बनाया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ने 2,469 संस्थानों को शामिल किया है और 32 करोड़ से ज्यादा पहचान पत्र जारी किए हैं, जिनमें से 2.36 करोड़ विशिष्ट अपार (एपीएआर) पहचान पत्र पहले ही क्रेडिट के साथ सीडेड हैं। 153 विश्वविद्यालयों में बहु-प्रवेश और निकास विकल्पों की शुरूआत, जबकि यूजीसी द्वारा अनुमोदित द्विवार्षिक प्रवेश, भारत को 2035 तक अपने 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, 116 उच्च शिक्षा संस्थान 1,149 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, जिससे 19 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

साथ ही 107 संस्थान 544 ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। स्वयम (एसडब्लयूएवाईएएम) प्लेटफार्म अब 40 प्रतिशत तक क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें 388 विश्वविद्यालय इसके पाठ्यक्रमों को एकीकृत कर रहे हैं।

भाषा विश्वविद्यालय में नवीन सत्र हेतु ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित, पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा रहीं मुख्य अतिथि

लखनऊ : भाषा विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय में सत्र 2025-26 के B.A.LL.B, LL.B एवं LL.M पाठ्यक्रमों में नवप्रवेशित छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की प्रथम महिला दिव्यांग पर्वतारोही एवं पद्मश्री सम्मानित डॉ. अरुणिमा सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अपने प्रेरणादायक व्याख्यान में डॉ. सिन्हा ने छात्रों को जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश दिया। उनके जीवन संघर्ष और उपलब्धियों को सुनकर छात्रों में आत्मविश्वास व नई ऊर्जा का संचार हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने की। उन्होंने छात्रों को विधि क्षेत्र की विभिन्न संभावनाओं से परिचित कराते हुए विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया।

विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष त्रिवेदी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए छात्रों को अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास के महत्व को रेखांकित किया।

इस अवसर पर विधि अधिष्ठाता प्रोफेसर मसऊद आलम, कुलसचिव डॉ. महेश कुमार, उप कुलसचिव श्री मोहम्मद साहिल, कुलानुशासक डॉ. नीरज शुक्ला सहित विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकगण एवं अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

ओरिएंटेशन कार्यक्रम में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे अपने करियर की दिशा में मार्गदर्शक बताया।

पश्चिम रेलवे द्वारा बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया बांद्रा स्टेशन महोत्सव

स्टेशन महोत्सव में भव्य बांद्रा स्टेशन की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक पहचान का जश्न मनाया गया

मुंबई,

बांद्रा स्टेशन की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा एक जीवंत कार्यक्रम "बांद्रा स्टेशन महोत्सव" मनाया गया। 26 जुलाई, 2025 को आयोजित इस भव्य समारोह की शुरूआत पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह, मुंबई क्षेत्र की डाक सेवा की निदेशक श्रीमती कैया अरोड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक विशेष स्मारक कवर के अनावरण के साथ हुई। विशेष कवर का अनावरण एक मार्मिक क्षण था, जो इस प्रतिष्ठित स्टेशन की ऐतिहासिक विरासत के प्रति एक सच्चा सम्मान था।

(पहली पंक्ति - पहली एवं दूसरी तस्वीरें) पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह, मुंबई क्षेत्र की डाक सेवा की निदेशक श्रीमती कैया अरोड़ा विशेष स्मारक कवर का अनावरण करते हुए। (दूसरी पंक्ति) "आर्ट एंड क्राफ्ट" और "व्लॉग मेकिंग" प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ गणमान्य व्यक्ति।

बांद्रा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शानदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य प्रदर्शन और ऊजार्वान कराओके प्रस्तुतियाँ शामिल थीं, जिन्होंने उत्सवी माहौल को और भी समृद्ध बना दिया। इस दिन का मुख्य आकर्षण "आर्ट एंड क्राफ्ट" और "व्लॉग मेकिंग" प्रतियोगिताओं के लिए बेसब्री से प्रतीक्षित पुरस्कार वितरण समारोह था। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को उनके कलात्मक और नवोन्मेषी कौशल के साथ-साथ आकर्षक कहानी कहने की कला के लिए सम्मानित किया गया। इन रचनात्मक कृतियों ने बांद्रा स्टेशन की भावना और उसके जीवंत उत्साह को खूबसूरती से दशार्या।

बांद्रा स्टेशन महोत्सव ने विरासत के उत्सव को सामुदायिक भागीदारी के साथ मिश्रित किया, जिससे इस अवसर की स्थायी यादें बनीं, जो पुरानी यादों, रचनात्मकता और सौहार्द से भरी थीं। जून 2025 में शुरू हुआ यह महोत्सव एक लुभावने समापन के साथ संपन्न हुआ, जब सैकड़ों हीलियम गुब्बारे आकाश में उड़े, जिसने उत्सव की खुशी की भावना को पूरी तरह से दशार्या।

बांद्रा रेलवे स्टेशन मुंबई के बेहतरीन उपनगरीय रेलवे स्टेशनों में से एक है। अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध, यह लाखों दैनिक यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसे महाराष्ट्र सरकार के 1995 के विरासत नियमों में ग्रेड क विरासत संरचना के रूप में अधिसूचित किया गया है। एक सदी से भी अधिक पुराना रेलवे स्टेशन, यह विक्टोरियन गोथिक और स्थानीय शैली का एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प मिश्रण है, जो अपने स्थल पर एक प्रमुख लैंडमार्क के रूप में उभर कर आता है। बांद्रा स्टेशन 28 नवंबर, 1864 को खोला गया था। हालाँकि, शानदार विरासत बांद्रा स्टेशन भवन 24 साल बाद 1888 में बनाया गया था।

भारत रेलवे उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बनता जा रहा है

माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात के वडोदरा के सावली स्थित एल्सटॉम कारखाने का दौरा किया।

मंत्री महोदय के साथ वडोदरा के सांसद डॉ. हेमांग जोशी, सावली के विधायक श्री केतन इनामदार, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, वडोदरा और अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी मौजूद थे।

नमो भारत कोचों का उत्पादनः एल्सटॉम कारखाने में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने रेल मंत्री को कारखाने में चल रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी।

मंत्री महोदय ने अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित 'नमो भारत' कोचों के आधुनिक डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता की सराहना की।

(रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और वडोदरा के सांसद डॉ. हेमांग जोशी, सावली कारखाने में निर्मित 'नमो भारत' कोचों के संबंध में एल्सटॉम के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए)

समग्र रखरखाव गतिविधियाँः एल्सटॉम टीम ने मंत्री को रखरखाव गतिविधियों, जिनमें सामग्री का उपयोग और आपूर्तिकर्ता एकीकरण शामिल है, के बारे में जानकारी दी। चचाओं में सेंसर और एआई का उपयोग करके निवारक रखरखाव भी शामिल था।

मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड

रेल मंत्री को कंपनी के हर ऑर्डर के साथ उपकरणों के डिजाइन को निरंतर उन्नत करने के अभिनव दृष्टिकोण से अवगत कराया गया। मंत्री ने एल्सटॉम को उसके 'डिजाइन इन इंडिया' रेलवे उपकरणों के लिए बधाई दी।

कारखाने में निर्मित कोच, लोकोमोटिव, बोगियां, प्रणोदन प्रणालियाँ आदि दुनिया भर में निर्यात की जाती हैं। ये रेलवे उपकरण 'डिजाइन, डेवलप, डिलीवर फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड इनिशिएटिव' के तहत ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, मैक्सिको और अन्य देशों तक पहुँच रहे हैं।

"भारत में रेलवे निर्माण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन का प्रभाव देख रहा है। भारत अब दुनिया के कई विकसित देशों को रेलवे के कलपुर्जे, कोच और लोकोमोटिव निर्यात कर रहा है", मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता पर रेल मंत्री ने कहा।

सावली कारखाने ने वडोदरा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का सृजन किया है और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दिया है।

भारत में प्रतिभा विकास, विश्व के लिए

मंत्री को भारत में एल्सटॉम द्वारा की जा रही प्रतिभा विकास गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि भारत में एल्सटॉम के लगभग 7,000 इंजीनियर हैं, जिनमें रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग सिस्टम दोनों शामिल हैं। इनमें से लगभग 300 इंजीनियर अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में कार्यरत हैं।

मंत्री ने एल्सटॉम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रुचि व्यक्त की और गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ सहयोग का सुझाव दिया। उन्होंने एल्सटॉम, सावली और पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के बीच मौजूदा प्रशिक्षण साझेदारी की सराहना की।

मंत्री ने एल्सटॉम टीम से भारतीय रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर ऑफ-कैंपस और ऑन-साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और उनकी टीमों को इन कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

एमएसएमई के लिए नया डिजिटल क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल उसके ऋण अनुमोदन को तेज करने के लिए वास्तविक समय के डिजिटल डेटा का लाभ उठाता है

(जीएनएस)।

केंद्रीय बजट 2024-25 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के लिए नए डिजिटल ऋण मूल्यांकन मॉडल की घोषणा की गई थी। इस मॉडल में यह परिकल्पना की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स के स्कोरिंग के आधार पर एक नया

ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने 6 मार्च, 2025 को एमएसएमई के लिए नए ऋण मूल्यांकन मॉडल का शुभारंभ किया था।

यह मॉडल डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का लाभ उठाता है और सभी ऋण आवेदनों के लिए वस्तुनिष्ठ निर्णय और बैंक के लिए मौजूदा (ईटीबी) और बैंक के लिए नए (एनटीबी) एमएसएमई उधारकताओं दोनों के लिए मॉडल-आधारित सीमा मूल्यांकन का उपयोग करके एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित यात्रा तैयार करता है।

इस मॉडल में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल फुटप्रिंट में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) का इस्तेमाल करके पैन प्रमाणीकरण, ओटीपी का इस्तेमाल करके मोबाइल और ईमेल सत्यापन, सेवा प्रदाताओं के जरिए ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) से जीएसटी डेटा प्राप्त करना, अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करके बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, आईटीआर अपलोड और सत्यापन, एपीआई सक्षम वाणिज्यिक और उपभोक्ता ब्यूरो प्राप्त करना और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) का इस्तेमाल करके उचित परिश्रम, एपीआई के जरिए धोखाधड़ी की जांच आदि शामिल हो सकते हैं। यह मॉडल अलग-अलग ऋण राशि की सीमा वाले सभी बैंकों पर लागू होगा।

पारंपरिक/मैन्युअल पद्धतियों के अंतर्गत बैंक मैन्युअल अंडरराइटिंग के लिए ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत भौतिक दस्तावेजों पर निर्भर रहते हैं, जबकि नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के अंतर्गत क्रेडिट अनुरोध और डेटा प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ मूल्यांकन पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

वडनगर सिटी के समीप रेलवे अंडरपास संख्या 41ए, 30 सितंबर तक बंद रहेगा

अहमदाबाद मंडल के महेसाणा-तारंगा रेलखंड पर वडनगर सिटी के समीप स्थित रेलवे अंडरपास (फ्वइ) संख्या 41अ (केसीम्पा खेतों का मार्ग विस्तार) को मानसून के दौरान 30 सितंबर तक आमजन के लिए बंद कर दिया गया है।

भारी वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति को देखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा और रेलवे संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जनहित एवं सुचारु तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

विसनगर के समीप रेलवे अंडरपास 16 डी एवं 22ए, 30 सितंबर तक बंद रहेगा

अहमदाबाद मंडल के महेसाणा-तारंगा रेलखंड पर स्थित रेलवे अंडरपास (फ्वइ) संख्या 16ऊ (शेरडीनगर से कांसा विस्तार मार्ग) एवं फ्वइ संख्या 22अ (मस्तान नगर सोसायटी, वडनगर दरवाजा) को मानसून के दौरान 30 सितंबर 2025 तक आमजन के लिए बंद किया गया है।

भारी वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति को देखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा और रेलवे संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जनहित एवं सुचारु तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थापना दिवस पर भारत की जलवायु तैयारी संबंधी प्रमुख पहल घोषित किए

(जीएनएस)।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जलवायु-अनुकूल और वैज्ञानिक रूप से सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा विकसित नए वैज्ञानिक उपकरण और डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने विज्ञान-संचालित सेवाओं के प्रति गहन जन सहभागिता और व्यापक जागरूकता का आह्वान किया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में मंत्रालय के कामकाज, इसकी पहुंच और लोगों के जीवन पर इसके वास्तविक प्रभाव से उल्लेखनीय बदलाव आया है।

डॉ. सिंह ने कहा कि विज्ञान और नवाचार पारिस्थितिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ ही आगामी दशकों में भारत के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां एक सामान्य उपयोगकर्ता भी अपने मोबाइल फोन पर लाइव मौसम अलर्ट, चक्रवात संबंधी चेतावनी, वायु गुणवत्ता अपडेट और समुद्री पूवार्नुमान की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह मिशन मोड में काम करने वाली सरकार और एक ऐसे मंत्रालय के कार्य परिणाम हैं, जिसने स्वयं को नागरिक सेवा केंद्रित संस्थान के रूप में ढ़ाल लिया है।"

इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित 14 प्रमुख उत्पादों और पहल का औपचारिक शुभारंभ किया। इनमें वर्षा निगरानी और फसल-मौसम कैलेंडर, भारत पूवार्नुमान प्रणाली - विस्तारित अवधि पूवार्नुमान (भारतएफएस-ईआरपी) जैसी उन्नत मौसम पूवार्नुमान प्रणालियां, उच्च-रिजॉल्यूशन वर्षा डेटासेट, अद्यतन तरंग एटलस और समुद्र तल चार्ट, वायु गुणवत्ता पूवार्नुमान प्रणालियां, समुद्री जैव विविधता रिपोर्ट और चार भारतीय शहरों के भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण अध्ययन शामिल हैं। इस मौके पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्मित "लाइफ सेविंग इम्पैक्ट" नाम की एक नई डाक्यूमेंटरी (वृत्तचित्र) भी रिलीज की गई।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पिछले दस वर्षों में आये व्यापक बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में आज डॉप्लर मौसम रडार की संख्या 15 से बढ़कर 41 हो गई है। इसी तरह, भूकंपीय और मौसम केंद्र, ऊपरी वायु प्रेक्षण प्रणालियां, आकाशीय बिजली

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, सिस्टम का खेल निराला, जिम्मेदारों ने लगाई फर्जी रिपोर्ट

लेखपाल ने आरोपी को ही बनाया गवाह, पुलिस ने शिकायत कर्ता पर की कार्रवाई।

आजमगढ़ : शासन के निदेर्शानुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त करना है और भूमि को कब्जे मे लेते हुए वहाँ सरकारी जमीन का बोर्ड लगा देना चाहिए लेकिन राजस्व कर्मचारी इसके विपरीत कार्य करते हुए सुविधा शुल्क लेकर अधिकारियों को भ्रामक रिपोर्ट भेजकर गुमराह करते रहते है। वही इस काम मे पुलिस भी पीछे नही है वहां तो शिकायत कर्ता पर ही कार्यवाही करते हुए भ्रामक रिपोर्ट लगा अपने आका को गुमराह करते है। शासन प्रशासन इन नीचे के कर्मचारियों का कटपुतली बनकर रह जता है।

ताजा मामला ग्राम बस्ती भुजबल परगना कौड़िया तहसील बूढ़नपुर आजमगढ़ का है।

बताते चले कि बीते जून माह की 13 तारिख को ग्राम बस्ती भुजबल, परगना कौड़ियां, तहसील बूढ़नपुर जिला आजमगढ़ में गाटा संख्या 161 रकबा 0.024 हे० की नवीन

लेखपाल की रिपोर्ट कोई निर्माण नहीं।

सीओ की रिपोर्ट, निर्माण रुकवा दिया गया है।

परती/सरकारी भूमि पर नीरज गुप्ता ऊर्फ नीरज मोदनवाल पुत्र दिनेश मोदनवाल और दिनेश मोदनवाल, योगेन्द्र यादव ऊर्फ बाबूलाल यादव अपने सहयोगियों के साथ राजस्व कर्मियों एव पुलिस की मिलीभगत से अवैध कब्जा किया जा रहा है। जिसकी सूचना जागरूक नागरिक अंसल ने एन्टी भू माफिया पर शिकायत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से किया था जिसकी जांच क्रम लेखपाल कानूनगो ने आरोपी को ही गवाह बनाते हुए नवीन परती पर कोई कब्जा न होने और नहर की पटरी की फोटो लगाकर रिपोर्ट लगा दिया।

वहीं सी ओ बूढ़नपुर ने घटना के दिन की फोटो लगाकर काम रुकवाने और कोई कब्जा न होने की रिपोर्ट लगाया है। जबकि मौके पर दिवाल उठाकर कब्जा किया गया है।

कानून गो ने धमकाया,पुलिस ने की शांति भंग में की कार्रवाई।

राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगाने पर शिकायत कर्ता ने पुनः मुख्मयंत्री पोर्टल पर शिकायत किया तो बौखलाए राजस्व निरीक्षक ने शिकायत कर्ता से काल कर अभद्रता भाषा का प्रयोग किया।

वहीं स्थानीय पुलिस थाना अहरौला ने शिकायत कर्ता के पिता पर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। शिकायत कर्ता के पिता लखनऊ मे रहते है।

शिकायत कर्ता के पिता दयाशंकर चौबे ने आजमगढ़ के राजस्व कर्मचारी एवं पुलिस की भ्रामक रिपोर्ट लगाने को मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत किया है।

ऑपरेशन सिंदूर का समग्र राजनीतिक-सैन्य उद्देश्य पाकिस्तान को उसके छद्म युद्ध के लिए दंडित करना था : रक्षा मंत्री

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 जुलाई, 2025 को लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सीमा पार करना या शत्रु क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान द्वारा वर्षों से पोषित आतंकी ढांचे को नष्ट करना और सीमा पार से किये गये हमलों में अपने प्रियजनों को खोने वाले निर्दोष परिवारों को न्याय दिलाना था। श्री सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अचानक आवेश से भरा पागलपन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति और पुरानी कुंठा बताया और इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का समग्र राजनीतिक-सैन्य उद्देश्य आतंकवाद के छद्म युद्ध लड़ने वाले पाकिस्तान को दंडित करना था।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता, बल्कि अपने राष्ट्रीय संकल्प, नैतिक बल और राजनीतिक कौशल का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत किसी भी आतंकवादी हमले का निर्णायक और स्पष्ट जवाब देगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पनाह और समर्थन देने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेलिंग या अन्य दबावों के आगे झुकने वाला नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को, अमानवीयता का सबसे घिनौना उदाहरण बताया, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर मार डाला गया। यह भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि हमले के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को विवेक, रणनीतिक समझ और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का ध्यान रखते हुए निर्णायक कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर आरंभ किया, जो सिर्फ. एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, अस्मिता और देश के लोगों के प्रति सरकार के दायित्व और आतंकवाद के विरुद्ध उसकी प्रभावी नीति का निर्णायक प्रदर्शन था।

उन्होंने कहा कि हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल परिपक्वता दिखाई, बल्कि वैसी रणनीतिक बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की, जिसकी भारत जैसी ज़िम्मेदार शक्ति से अपेक्षा की जाती है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने हर पहलू का गहराई से अध्ययन के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया।

भारी उद्योग मंत्रालय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया

(जीएनएस)।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया।

इस अवसर पर भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकी भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिजवी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सीपीएसई के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक, स्वायत्त निकायों और मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न उद्योग संघों एवं परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस मौके पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरासत और योगदान को श्रद्धांजलि स्वरूप एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें की को एक दृश्य दी गई। यह फिल्म उनके जीवन की दुर्लब झलकियों और प्रभावशाली वर्णन के माध्यम से उन्हें एक राष्ट्र निमार्ता और दूरदर्शी नेता के रूप में

प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से भारत के औद्योगिक विकास की नीव रखने में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है।

अपने संबोधन में मंत्री महोदय ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में और बाद में केंद्रीय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में डॉ. मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री वर्मा ने देश के औद्योगिक और संस्थागत विकास में डॉ. मुखर्जी के मूलभूत योगदान को भी रेखांकित किया और उन्हें एक प्रखर विद्वान, राजनेता, निर्भिक सांसद और शिक्षाविद् के रूप में याद किया - जिनका जीवन साहस, दृढ़ विश्वास और "एक राष्ट्र, एक संविधान" में अटूट विश्वास का एक कालातीत प्रतीक बना हुआ है।

उद्घाटन भाषण देते हुए भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिजवी ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए डॉ. मुखर्जी के विजन पर बल दिया, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनाने पर उनके जोर को रेखांकित किया।

इस अवसर पर आमंत्रित वक्ता श्री बिनय कुमार सिंह, जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक है, ने डॉ. मुखर्जी के जीवन और विरासत पर एक विचारोत्तेजक व्याख्यान दिया। उनके सम्बोधन ने डॉ. मुखर्जी के मूल्यों, विजन और बहुआयामी योगदान की गहरी समझ प्रदान की और भावी पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

तर्कसंगत सुझाव

सराहनीय सुझाव दिल्ली की मुख्यमंत्री सुश्री रेखा गुप्ता ने पेट्रोल की 15 और डीजल की 10 वर्ष पुराने वाहनों को ईंधन न देने के प्रादूषण नियंत्रण निकाय के पैसले पर तत्काल रोक तो लगवाई ही साथ ही उन्होंने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस समस्या को लेकर जो सुझाव देने का पैसला किया है, वह न सिर्प तर्वसंगत है बल्कि सराहनीय भी है। मुख्यमंत्री ने अपने सुझाव की जानकारी देते हुए शनिवार को कहा कि यदि उम्र के आधार पर वाहनों को हटाने का 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाए तो इस अव्यावहारिक आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के पहले के जो वाहन प्रादूषण पैलाते हैं, वे बच जाएंगे और निर्धारित अवधि के बाद के जो वाहन प्रादूषण नहीं पैलाते क्योंकि उनके अच्छी तरह रखरखाव या कम चलाने के कारण प्रादूषण नहीं फैलाते। वे सड़क से हट जाएंगे। इस अतार्विक एवं अव्यावहारिक अपने 2018 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट वापस ले और सड़क से उन्हीं वाहनों को हटाया जाए जो प्रादूषण फैलाते हों भले ही उनकी उम्र 5 वर्ष ही क्यों न हो। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में यदि मुख्यमंत्री गुप्ता का यह सुझाव मान लिया गया तो चालक वाहन की नियमित प्रादूषण सर्टिफिकेट रखने के प्राति सतर्व भी हो जाएंगे। सच में जब राजनेता संवेदनशील तरीके से पैसले लेते हैं तो जनता में उन्हें लोकप्रियता हासिल होती है लेकिन जो लकीर के फकीर होते हैं वे समझदारी से पैसले नहीं ले पाते और उनकी इसी नासमझी का परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बीएसएनएल के प्रदर्शन की समीक्षा की, ग्राहकों की सुविधा और राजस्व सृजन पर जोर दिया

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मुख्य महाप्रबंधकों (सीजीएम) के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में बीएसएनएल की परिचालन प्रगति की समीक्षा की गई, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान किया गया और कंपनी के नेटवर्क एवं सेवा वितरण के लिए आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में संचार राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर और दूरसंचार विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सत्रों के बीच मीडिया ब्रीफिंग में, श्री सिंधिया ने बताया कि इस बैठक में दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की भूमिका को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने पर चर्चा हुई।

विकास और आधुनिकीकरण पर जोर

समीक्षा के दौरान बीएसएनएल की विकास रणनीति, नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार, ग्राहक सेवा वितरण और संगठनात्मक आधुनिकीकरण पर व्यापक चर्चा हुई। इस व्यापक चर्चा ने बीएसएनएल की एक उपभोक्ता-केंद्रित दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में स्थिति को और मजबूत किया, जिसका स्पष्ट लक्ष्य सभी व्यावसायिक इकाइयों में "राजस्व सर्वोपरि" है। इस मंच ने बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन को हर स्तर पर इन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद की और परिणामों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया।

ग्राहक-प्रथम परिवर्तन

बीएसएनएल अपने सभी सर्किलों, व्यावसायिक क्षेत्रों और इकाइयों में सेवाओं में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अपने "ग्राहक सर्वप्रथम" सिद्धांत को आगे रखने के लिए बीएसएनएल सक्रिय ग्राहक जुड़ाव, बेहतर सेवा जवाबदेही और त्वरित शिकायत निवारण पर जोर दे रहा है।

प्रमुख फोकस क्षेत्र और परिणाम

सीजीएम बैठक के दौरान, बीएसएनएल के सर्किल प्रमुखों को ग्राहक तक पहुंच और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई। पहचाने गए विशेष फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

ग्रामीण, शहरी, उद्यम और खुदरा क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ फिर से जुड़ना

मोबाइल नेटवर्क और फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) में सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) में सुधार

बिलिंग, प्रावधान और नेटवर्क अपटाइम में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना

प्रत्येक परिचालन स्तर पर ह्लराजस्व-प्रथमह्व लक्ष्यों के साथ जवाबदेही को बढ़ावा देना

कनेक्टिविटी, वीपीएन समाधान, लीज्ड लाइन सेवाएं और अन्य नए व्यावसायिक अवसरों जैसी उद्यम सेवाओं का विस्तार करना।

श्री सिंधिया ने बीएसएनएल के प्रयासों की सराहना की और ग्राहकों को सुविधा तथा राजस्व सृजन में उल्लेखनीय सुधार लाने के महत्व पर बल दिया।

नई सेवा पहल

समीक्षा के दौरान, बीएसएनएल की हाल ही में शुरू की गई कई नई पहलों पर प्रकाश डाला गया, जिनका उद्देश्य सेवाओं की पेशकश और ग्राहक मूल्य में वृद्धि करना है। इन पहलों में शामिल हैं:

कई दूरसंचार सर्किलों में 4जी का विस्तार और रोलआउट

अगली पीढ़ी के इन्फोटेनमेंट के लिए मोबाइल ग्राहकों के लिए एफटीटीएच और बीआईटीवी प्लेटफॉर्म के लिए आईएफटीवी की शुरूआत

बीएसएनएल राष्ट्रीय वाई-फाई रोमिंग (ग्राहकों के लिए राष्ट्रव्यापी वाई-फाई रोमिंग सेवा)

उद्यम और सरकारी ग्राहकों के लिए अनुकूलित बीएसएनएल वीपीएन सेवाएं और बंडल पैकेज

मिशन-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में उच्च-विश्वसनीयता कनेक्टिविटी के लिए सीएनपीएन परियोजनाएं (निजी नेटवर्क पहल)

स्पैम -मुक्त नेटवर्क - घोटाले और स्पैम संचार को तत्क्षण समाप्त करने के लिए अपनी तरह का पहला समाधान

बीबीए (बीएसएनएल बिजनेस एसोसिएट) के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे शिक्षित युवा बीएसएनएल बिक्री चैनल को मजबूत बनाने और बिक्री कमीशन अर्जित करने में सक्षम होंगे।

डिजिटल रूप से सशक्त भारत की ओर

बीएसएनएल कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अब डिजिटल रूप से सशक्त, सेवा-उन्मुख और वित्तीय रूप से टिकाऊ दूरसंचार ऑपरेटर बनने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है। कंपनी पूरे देश में आधुनिक दूरसंचार सेवाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करके "भारत" को जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भागीदारी

(जीएनएस)।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 मई 2025 को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 10वीं बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक (सीएमएम) में अपनाई गई घोषणा अनुलग्नक में दी गई है।

ब्रिक्स मंच के अंतर्गत परिकल्पित पहलों का कार्यान्वयन राष्ट्र विशिष्ट है, न कि क्षेत्र विशिष्ट।

ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 10वीं बैठक की घोषणा

प्रस्तावना

हम, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, संघीय गणराज्य ब्राजील की अध्यक्षता में, "अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण देशों के सहयोग को मजबूती" विषय के तहत, हमारे सांस्कृतिक सहयोग एजेंडे में आगे की प्रगति की समीक्षा के लिए 26 मई 2025 को ब्रासीलिया शहर में बैठक की।

ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के अंतर्गत सर्वसम्मति, पारस्परिक सम्मान और समझ, खुलेपन, एकजुटता और संप्रभु समानता की ब्रिक्स भावना का पालन करना;

9 जुलाई 2015 को हस्ताक्षरित संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर ब्रिक्स देशों की सरकारों के बीच समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को याद करते हुए, और 24 मई 2022 को हस्ताक्षरित समझौते 2022-2026 के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना, साथ ही मारोपेंग घोषणा - 2018; क्यूरिटिबा घोषणा - 2019; मॉस्को घोषणा - 2020; नई दिल्ली घोषणा - 2021; बीजिंग घोषणा - 2022; म्पुमलंगा घोषणा - 2023; और सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा - 2024;

बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए सहयोग, संवाद और समझ बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए , ब्रिक्स सदस्यों और वैश्विक दक्षिण देशों की सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास दृष्टिकोण की बहुलता को स्वीकार करते हुए , जो अधिक टिकाऊ विश्व का पक्षधर है, और वैश्विक शासन में वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण को महत्व देते हुए ;

संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने, विरासत, नवाचार और रचनात्मकता को अत्यधिक महत्व देने, संयुक्त रूप से मजबूत अंतरराष्ट्रीय लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग की वकालत करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान;

रचनात्मकता, नवाचार, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर सतत विकास के प्रमुख प्रवर्तक और चालक के रूप में संस्कृति की शक्ति को मान्यता देना;

समाज के विकास के लिए संस्कृति के आंतरिक मूल्य पर प्रकाश डालना, चुनौतियों का सामना करना और डिजिटल वातावरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों सहित आईसीटी के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न अवसरों पर विचार करना;

सांस्कृतिक संपदा को उनके मूल देशों में वापस लौटाने से समाजों और राज्यों पर पड़ने वाले व्यापक सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार करते हुए, तथा इस संबंध में सभी उपाय करने की नैतिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए, ताकि सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने और अपनी सांस्कृतिक विरासत तक पहुंच बनाने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का पूर्ण आनंद सुनिश्चित किया जा सके;

इंडोनेशिया को शामिल करने और साझेदार देशों की श्रेणी की स्थापना के माध्यम से ब्रिक्स परिवार के विस्तार का स्वागत करते हुए, जो वैश्विक दक्षिण को शांति और साझा समृद्धि के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने में सक्षम बनाता है;

9 जुलाई 2015 को ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते को स्वीकार करने के लिए नए ब्रिक्स सदस्यों को प्रोत्साहित करना;

हम निम्नलिखित के माध्यम से अपने सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लेते हैं:

1. संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, कॉपीराइट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

1.1 सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों और उद्योगों के बढ़ते आर्थिक भार और आय, सभ्य रोजगार, रचनात्मक कौशल और नवाचार को बढ़ावा देकर समग्र अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देना;

1.2 संस्कृति पर ब्रिक्स कार्य समूह के अंतर्गत सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर एक ब्रिक्स मंच स्थापित करने पर सहमति; तथा सदस्यों, उनकी संबंधित सांस्कृतिक संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं, साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को उसके अधिदेश के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, ब्रिक्स सदस्य देशों की सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन और बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार करने, सांस्कृतिक सामग्री के प्रसार का विस्तार करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का विकास करने, कलाकारों और सांस्कृतिक व्यवसायियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, साथ ही रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना;

1.3 रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मापने के लिए मान्यता प्राप्त वैश्विक मानकों और संकेतकों के आधार पर ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण, मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय सांख्यिकीय संरचना बनाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना;

1.4 सभी के लिए एक नैतिक, सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी, भरोसेमंद, विकासोन्मुख, न्यायसंगत, पारदर्शी एआई की आवश्यकता की पुष्टि करें, जो राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर, लागू अंतरराष्ट्रीय कानून, सम् प्रभुता, मानवाधिकार और सभी महिलाओं तथा लड़कियों के सशक्तिकरण, भाषायी विविधता, सांस्कृतिक विरासत, उपभोक्ताओं और उपयोगकताओं की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करता हो;

1.5 एआई प्रणालियों के खनन, प्रशिक्षण और विकास में कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों द्वारा संरक्षित सामग्री के उपयोग के लिए पारिश्रमिक या लाइसेंस देने पर ब्रिक्स देशों के बीच अनुभव के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर जोर देना;

1.6 डिजिटल वातावरण में एक स्थायी सांस्कृतिक इको-सिस्टम की आवश्यकता की पुष्टि करें जो रचनाकारों, कलाकारों, लेखकों और अन्य अधिकार धारकों को प्रभावी ढंग से समर्थन और उचित पारिश्रमिक प्रदान करे, साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों को बनाए रखे, इस प्रकार एक सुलभ, समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण डिजिटल वातावरण को सक्षम करे, साथ ही कलात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा भी करे;

1.7 डिजिटल वातावरण में बहुभाषिकता का समर्थन करना और भाषायी और सांस्कृतिक विविधता को शामिल करने, बढ़ावा देने, सुरक्षा और संरक्षण के लिए बड़े भाषा मॉडल में उपयोग किए जाने वाले सभी एआई मॉडल के प्रशिक्षण डेटासेट की आवश्यकता की पुष्टि करें;

1.8 पुस्तकालयों, अभिलेखीय भण्डारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए सहयोग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

2. संस्कृति, जलवायु परिवर्तन और 2030 के बाद का विकास एजेंडा

2.1 सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर 2022 यूनेस्को विश्व सम्मेलन के अनुरूप, भविष्य के 2030 के बाद के विकास एजेंडे में संस्कृति को एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में शामिल करने के समर्थन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं;

2.2. 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी28) में वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए यूएई फ्रेमवर्क के अनुरूप, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता को पहचानना; और जलवायु गतिशीलता के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र की क्षमता पर विचार करना;

2.3 जलवायु प्रयासों में संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखने की वकालत करने में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए संस्कृति-आधारित जलवायु कार्रवाई के मित्रों के समूह (जीएफसीबीसीए) के प्रयासों पर ध्यान दें;

2.4 ब्रिक्स देशों के बीच निम्नलिखित कार्यों के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करना: (८) सांस्कृतिक प्रथाओं और विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए अनुकूली रणनीति विकसित करके और पारंपरिक ज्ञान, स्वदेशी लोगों के ज्ञान और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा निर्देशित जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे को डिजाइन करके जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रभावों से सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण करना; (८) समाज के सभी स्तरों पर स्थायी प्रथाओं, लचीलेपन और जलवायु-परिवर्तन-संवेदनशील व्यवहार को प्रोत्साहित करने में सांस्कृतिक क्षेत्र की भूमिका का समर्थन करना;

2.5 यूएनएफसीसीसी और उसके पेरिस समझौते के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, हम विकसित देशों से आग्रह करते हैं कि वे विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु वित्त प्रदान करने और जुटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें;

2.6 पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय कानूनी संरक्षण को मजबूत करने का आह्वान करें और डब्ल्यूआईपीओ में चल रही चचाओं पर ध्यान दें।

3. सांस्कृतिक संपदा की वापसी और सुरक्षा

3.1 सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक न्याय, सामंजस्य और सामूहिक स्मृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ पीढ़ियों के बीच ज्ञान प्रसार को मजबूत करने, ऐतिहासिक निरंतरता की रक्षा करने और राज्यों के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति को उनके मूल देशों में वापस करने के महत्व की पुष्टि करें।

3.2 सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के साथ-साथ विशेष रूप से अपने समुदाय की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत तक पहुंच के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करना।

3.3 सांस्कृतिक संपत्ति को उनके मूल देशों में वापस करने के महत्व को स्वीकार करते हैं और गैर-पदानुक्रमित, सहकारी आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए इसकी क्षमता को स्वीकार करते हैं, और हम इस मामले पर अधिक मजबूत अंतरराष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता को पहचानते हैं।

3.4 अनुभवों, राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, कानून और सफल मामलों को साझा करके, विरासत शिक्षा और संग्रहालय शिक्षा को बढ़ावा देकर, सरकारी उदाहरणों और शैक्षणिक विशेषज्ञों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करके, साथ ही क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुपक्षीय संगठनों में प्राथमिकताओं और नीतियों के बीच तालमेल बिठाकर सांस्कृतिक संपदा की वापसी के विषय में सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होना।

मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम

(जीएनएस)।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए, संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) की स्थापना की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा कार्यान्वित इस मिशन का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की इसकी क्षमता का दस्तावेजीकरण करना है।

आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एनएमसीएम ने जून 2023 में मेरा गाँव मेरी धरोहर (एमजीएमडी) पोर्टल शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गाँवों की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करना है। वर्तमान में 4.7 लाख गाँव अपने-अपने सांस्कृतिक पोर्टफोलियो के साथ पोर्टल पर लाइव हैं।

एमजीएमडी पोर्टल मौखिक परंपराओं, मान्यताओं, रीति-रिवाजों, ऐतिहासिक महत्व, कला रूपों, पारंपरिक भोजन, प्रमुख कलाकारों, मेलों और त्योहारों, पारंपरिक परिधानों, आभूषणों और स्थानीय स्थलों सहित सांस्कृतिक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है। इस पोर्टल में देश में हाशिए पर पड़े समुदायों और देश भर की कम-जानने वाली परंपराओं की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ भी शामिल हैं।

एनएमसीएम भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांस्कृतिक संपत्तियों का दस्तावेजीकरण और संवर्धन करके, इस मिशन का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

एमजीएमडी कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए लक्षित गाँवों की कुल संख्या 6.5 लाख है। इसमें पश्चिम बंगाल राज्य के 41,116 गाँव शामिल हैं। अब तक पश्चिम बंगाल के 5,917 गाँवों का मानचित्रण किया जा चुका है और संबंधित डेटा एमजीएमडी वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। शेष 35,199 गाँव दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में हैं।

अभी तक तमिलनाडु सहित राज्यवार उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई वित्तीय सहायता आवंटित/स्वीकृत नहीं की गई है।

वर्तमान में एमजीएमडी वेब पोर्टल पर 4.7 लाख गाँवों का डेटा अपलोड किया जा चुका है। यह डेटा पारंपरिक कला रूपों, अनुष्ठानों और लोक प्रदर्शनों सहित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की पहचान और संरक्षण में सहायक होगा।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

सीआईएल ने कोयला खदान अपशिष्ट में पाए जाने वाले दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की

(जीएनएस)।

सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) से एकत्रित कोयला-व्युत्पन्न फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश के नमूनों तथा ओवरबर्डन क्ले के नमूनों का सूक्ष्म तत्वों और दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के लिए विश्लेषण किया गया है और परिणाम दशार्ते हैं कि फ्लाई ऐश और क्ले में कुल आरईई लगभग 400 पीपीएम है।

इसके अलावा नेवेली स्थित एनएलसी इंडिया लिमिटेड की खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों से एकत्रित ओवरबर्डन, लिग्नाइट और फ्लाई ऐश के नमूनों का भी दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) और सूक्ष्म तत्वों के लिए विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में पाया गया कि ताप विद्युत संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश में आरईई (2100 मिलीग्राम/किग्रा) की सांद्रता होती है, जिसमें हल्की और भारी दोनों तरह की आरईई और 300 मिलीग्राम/किग्रा यिट्रियम की मात्रा शामिल होती है।

सरकार ने 29 जनवरी, 2025 को 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना को मंजूरी दी। इस मिशन के अंतर्गत ओवरबर्डन, टेलिंग, फ्लाई ऐश और रेड मड जैसे स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति पर केंद्रित पायलट परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीएमएम के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना हेतु दिशानिर्देशों को 6 अप्रैल, 2025 को मंजूरी दे दी गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला खदान अपशिष्ट में पाए जाने वाले दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाएं शुरू की हैं:

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोयला क्षेत्र से आरईई और अन्य आर्थिक संसाधनों के मूल्यांकन परिणाम बताते हैं कि कुल आरईई कम है, लेकिन भारी आरईई सामग्री अपेक्षाकृत अधिक है।

2. सिंगरौली कोयला क्षेत्र में गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) में सूक्ष्म तत्वों और आरईई सांद्रता के मूल्यांकन दशार्ते हैं कि आरईई की प्रकृति आशाजनक है (कोयला नमूनों में संपूर्ण कोयला आधार पर लगभग 250 पीपीएम और गैर-कोयला नमूनों में लगभग 400 पीपीएम की समृद्धि के साथ)। हालांकि आरईई का किफायती निष्कर्षण तकनीकी प्रगति और पैमाने की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

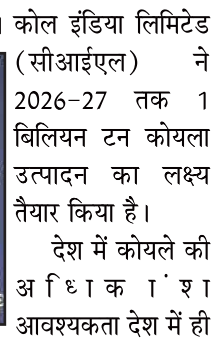

3. उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों के ऊपरी स्तरों से आरईई सहित महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, जिसका उद्देश्य (८) भौतिक पृथक्करण द्वारा गैर-कोयला स्तरों से महत्वपूर्ण धातुओं की संवर्धन तकनीक और (८) आयन-एक्सचेंज रेजिन द्वारा गैर-कोयला स्तरों और एसिड माइन ड्रेनेज से महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण तकनीक को विकसित करना है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), भुवनेश्वर; अलौह सामग्री प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी), हैदराबाद और आईआईटी, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

कोयला उत्पादन में वृद्धि

वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन पार कर चुका है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 2026-27 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य तैयार किया है।

देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता देश में ही कोयला उत्पादन से पूरी होती है। कोयले के आयात में मुख्य रूप से कोकिंग कोल और उच्च श्रेणी के गैर-कोकिंग कोल जैसे आवश्यक आयात शामिल हैं क्योंकि इनका घरेलू उत्पादन, या तो दुर्लभ भंडार या अनुपलब्धता के कारण सीमित है। भविष्य में कोयले की मांग को स्वदेशी स्रोतों से पूरा करने और कोयले के अनावश्यक आयात को कम करने के लिए, अगले कुछ वर्षों में घरेलू कोयला उत्पादन में सालाना 6-7 प्रतिशत की वृद्धि होने और 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

वर्ष 2024-2025 में देशभर में घरेलू कोयला उत्पादन 1047.67 मिलियन टन (अनंतिम) रहा जबकि वर्ष 2023-2024 में यह 997.83 मिलियन टन था। यानी लगभग 4.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 0.94 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 773.81 मिलियन टन की तुलना में 781.07 मिलियन टन (अनंतिम) कोयला उत्पादन किया।

सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने और देश में कोयले के अनावश्यक आयात को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख पहलों में एकल खिड़की मंजूरी, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 में संशोधन, जिससे कैप्टिव खदानों को अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति मिल सके, एमडीओ मोड के माध्यम से उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकों का उपयोग बढ़ाना, नई परियोजनाएं और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार और वाणिज्यिक खनन के लिए निजी कंपनियों/सार्वजनिक उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी शामिल है। वाणिज्यिक खनन के लिए सौ प्रतिशत (100 प्रतिशत) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है।

(क) कोयला आयात के विकल्प के रूप में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) मानक आवश्यकता के 100 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है, खासकर उन मामलों में जहां एसीक्यू को गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों के लिए मानक आवश्यकता के 90 प्रतिशत तक घटाया गया था या जहां एसीक्यू को तटीय विद्युत संयंत्रों के लिए मानक आवश्यकता के 70 प्रतिशत तक घटाया गया था। एसीक्यू बढ़ने से घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

वर्ष 2020 में आरंभ की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में बदलाव द्वारा, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक बढ़ाने से कोयला आयात में कमी लाने पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।

पुत्री पैदा होने पर नाराज पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

(जीएनएस)। बिजनोर क्षेत्र धामपुर थाना छेत्र से

एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां बेटी पैदा होने पर पति ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी, इतना ही नहीं वल्कि परिजनों को सूचना दिए बगैर ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुए है। यह पूरा मामला धामपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव गजरौला का है। यहां के रहने वाले मुकुल चौहान की शादी नजीबाबाद के रहने वाले माधो राम की बेटी रूबी से दो साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी हुई थी। पिता ने अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक काफी दान दहेज दिया था। लेकिन मुकुल चौहान उसके साथ इतने पर भी मारपीट करता रहता था। लेकिन मृतक रूबी सब सहती रही। इन्हीं ताना कशी के चलते पंद्रह दिन पहले रूबी ने एक बेटी को जन्म दिया। जिसके बाद आरोपी पति पुत्री पैदा होने का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया। और शनिवार की रात किसी समय उसने अपनी पत्नी रूबी की गला घोटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं वल्कि पत्नी के परिजनों को सूचना दिए बगैर ही आरोपी पति ने मृतक रूबी के शव को शेरकोट खो बेराज पर ले जाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब परिजनों को इस घटना का पता चला, तो कोहराम मच गया। परिजन लड़की रूबी की ससुराल पहुंचे तो गेट पर ताला लटका हुआ था। मगर मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर इस पूरी घटना की जानकारी मृतक रूबी के माता-पिता को दी। मृतक रूबी के माता-पिता ने इस खौफनाक घटना की जानकारी पुलिस को दी, उधर पुलिस का कहना है कि आरोपी मुकुल चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है।

मृतक रूबी के माता-पिता का कहना हैकि आरोपी मुकुल चौहान शादी के बाद से ही मृतका के साथ मारपीट करता था । एक बार उसने मृतका के साथ मारपीट कर बिना पैसे दिए नजीबाबाद के लिए बस में बिठा दिया था।जब भी मृतक रूबी ने किसी के फोन से घर पर सूचना दी थी, तब जाकर परिजन उसे लेने पहुंचे थे। उधर घटना के बाद फॉरेंसिक टीम शेरकोट श्मशान घाट स्थल पर पहुंची और कुछ अवशेष जांच के लिए अपने साथ ले गई।

95 वर्षीय बुजुर्ग की जमीन पर जबरन बनवाना चाहते रास्ता

(जीएनएस)। लखनऊ सरोजिनी नगर तहसील लाल नगर हरदोईया में पीड़ित के अनुसार पीड़ित की करीब दो बीघा जमीन है,जिसमें से जबरन निकालना चाह रहे हैं रास्ता।पीड़ित ने बताया ग्राम प्रधान पति नागेंद्र यादव द्वारा पीड़ित पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जबरन निकलना चाह रहे हैं रास्ता। ग्राम प्रधान पति नागेंद्र यादव से परेशान पीड़ित ने उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। वही जब इस संबंध में ग्राम प्रधान नागेंद्र

यादव से बात की गई उन्होंने बताया हम कोई रास्ता नहीं निकलवा रहे हैं रास्ता तहसील प्रशासन निकलवा रहे है।वही संबंध में लेखपाल सुनील कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान की शिकायत पर नपाई की गई है नपाई के दौरान गेंदा प्रसाद की जमीन पीछे की ओर निकल रही है गेंदा प्रसाद की जमीन से लगभग आठ फिट चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा।पीड़ित ने उप जिला अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय मांगा

सीएचसी स्योहारा में मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस ...

(जीएनएस)। डॉ0 स्नेही शासन से प्राप्त निदेशों के तहत आज सीएचसी स्योहारा में अधीक्षक डॉ 0बी 0के 0स्नेही की अध्यक्षता में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया जिसमें समस्त कर्मचारियों ने भाग लिया ।इस दौरान डॉ स्नेही ने बताया कि हर साल 28 जुलाई यानि की आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को लिवर से जुड़ी इस खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक करना. हेपेटाइटिस साइलेंट किलर की तरह काम करता है जो अक्सर बिना लक्षण शरीर के भीतर गंभीर नुकसान पहुंचा देता है. अगर समय रहते इसके संकेतों को पहचान लिया जाए तो इलाज और रोकथाम दोनों संभव हैं। हमारे यहां जांच की सुविधा उपलब्ध है ।इलाज के लिए सीएचसी धामपुर में ट्रीटमेंट सेंटर बना हुआ है जहां से दबाए मिलती है। वायरल लोड की सुविधा है जिले स्तर पर उपलब्ध है ।इसका मुख्य उद्देश्य हेपेटाइटिस के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. यह बीमारी लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वे इससे

संक्रमित हैं. इस वर्ष की थीम है पेटाइटिस से जुड़े भ्रम और रुकावटों को तोड़ना है ताकि सभी को इलाज, टेस्ट और टीकाकरण तक आसान पहुंच मिल सके. हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है जैसे कि हेपेटाइटिस ए: दूषित भोजन या पानी से फैलता है. हेपेटाइटिस बी : संक्रमित खून, शरीर के अन्य तरल पदार्थों (जैसे असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुइयों का उपयोग) से फैलता है. हेपेटाइटिस सीः मुख्य रूप से संक्रमित खून के संपर्क में आने से फैलता है (जैसे संक्रमित सुइयों या रक्त चढ़ाने से). हेपेटाइटिस डीः यह केवल उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी है. हेपेटाइटिस ईः दूषित पानी या भोजन से फैलता है. हेपेटाइटिस के शुरूआती लक्षण निम्न होते हैं? शुरूआती लक्षण हल्के हो सकते हैं या बिलकुल भी दिखाई नहीं देते जिसकी वजह से इसे साइलेंट किलर कहते हैं.इसके सामान्य लक्षण इस प्रकार होते हैं.

* थकान
* जी मिचलाना और उल्टी
* पेट दर्द (खासकर ऊपरी दाहिने हिस्से में)
भूख न लगना
* हल्का बुखार
* पेशाब का रंग गहरा होना
* आंखों और त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया)
* जोड़ों में दर्द
* मिट्टी के रंग का मल

हां हेपेटाइटिस के कई प्रकारों का इलाज संभव है.हेपेटाइटिस ए और ई अक्सर अपने आप ठीक हो जाते हैं. हेपेटाइटिस बी और सी के लिए प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं जो बीमारी को नियंत्रित कर सकती हैं और कुछ मामलों में पूरी तरह ठीक कर सकती हैं. हेपेटाइटिस का इलाज संभव है टीकाकरणः हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीके उपलब्ध हैं.स्वच्छताः खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं. साफ पानी पिएं.सुरक्षित यौन संबंधः कंडोम का इस्तेमाल करें.सुइयों का साझा उपयोग न करेंः ड्रग्स लेने, टैटू बनवाने या कान छिदवाने के लिए कभी भी इस्तेमाल की हुई सुइयों का उपयोग न करें. रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों से बचेंः संक्रमित खून के संपर्क में आने से बचें. इस दौरान हैल्थ सुपरवाइजर वीर सिंह, राजेश कुमार, फार्मासिस्ट योगेश कुमार,हरीश कुमार,प्रदीप रावत , जितेंद्र रावत, बीपीएम शालिनी बिश्नोई, डी ओ राशि,अनम आदि उपस्थित रहे।

उन्नाव में बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ

(जीएनएस)। औरास उन्नाव। अज्ञात चोरों के द्वारा सुने पड़े घर से घर का ताला तोड़कर कमरे में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए के सामान चोरी कर ले गए सूचना पर पहुंची पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। औरास थाना क्षेत्र के नेवरा उदई मजरे अरसेना गांव निवासी दिनेश पुत्र वासुदेव, मिश्रीलाल पुत्र परागी लाल, संतोष पुत्र मिश्रीलाल व सहित पांच घरों में अज्ञात चोरों के द्वारा सूने पड़े घर का ताला तोड़कर घर में रखें सोने चांदी के जेवरात सहित नगदी व अन्य सामान अज्ञात चोरों के द्वारा पर कर दिया गया

सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांचो घर में हुई चोरी में अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है किंतु अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चल सका है। रात भर गस्त होने के बावजूद चोरों के द्वारा बड़ी संख्या में चोरी की घटना का अंजाम दिया गया पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस को अज्ञात चोरों के विरुद्ध लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी भवन सिंह मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चोरी की घटनाएं हुई है किंतु पीड़ित की तरफ से तहरीर नहीं दिया गया है।

बैठक में क्षेत्रीय किसानों मजदूरों ने अपने अपने सम्बोधन कई मुद्दे रखें

राजधानी लखनऊ भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन के जिला कैम्प कार्यलय गोसाईगंज सुल्तानपुर रोड प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने वर्मा मार्केट पर मासिक बैठक सम्पन्न हुई बैठक में क्षेत्रीय किसानों मजदूरों ने अपने अपने सम्बोधन कई मुद्दे रखें जैसे सिंचाई हेतु नहर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं इंडिया टू मार्का हैंडपंप विकलांग पेंशन वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन विकलांग आवास शौचालय आवास राशन कार्ड लेबर कार्ड आयूष मान कार्ड बिजली कटौती बढ़ा हुआ बिजली पुलिस गांव में गस्त नहीं कर रही और पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे जो लिखा जा रहे हैं मैं उनकी घोर निंदा करता हूं हमारा

संगठन पत्रकारों के साथ खड़ा है अवैध कब्जा अवैध खनन सफाई व्यवस्था अस्पताल दवाई छिड़काव गांवों में नहीं स्टील लाईट खराब नाली खंडजा कच्चा रास्ता सी सी रोड निर्माण नये निर्माण मरम्मत कार्य कराया जाये राजस्व विभाग में लम्बे समय से चल रहें मुकदमों को फैनल किया जाये पूर्वांचल चौराहा सुल्तानपुर रोड चांद सराय मोड पुल के नीचे अवैध तरीके से लगी दुकानों को हटाया जाए जिससे आने जाने वालों को कठिनाई का समान करना पड़ता है 24 घंटे जाम रोड पर जाम लगा रहता है कई घटनाएं घट चुकी है कई जाने जा चुकीं हैं काफी संख्या में लोग चोटिल पड़े अस्पताल में ईलाज करा रहे हैं खाद बीज दवाई उपलब्ध नहीं यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाए सच की आवाज को उठाने वाले प्रतकारो पर जान से मार देने का हमला और फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेजा जा रहा यह कार्य निंदनीय है और संगठन का विस्तार प्रचार प्रसार किसान मजदूर समस्याओं पर चर्चा हुई किया इन सभी मुद्दों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट लखनऊ पर बडा आंदोलन किया जायेगा पंचायत में उपस्थित संगठन के जिला अध्यक्ष सरदार सिंह गौतम जिला उपाध्यक्ष मिलन गोमती प्रसाद पूर्व प्रधान

भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की दसवीं पुण्य तिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई।

(जीएनएस)। वाराणसी 28/07/2025 दिन सोमवार को सरैया में कांग्रेस कैंप कार्यालय में पूर्व पार्षद वर्तमान पार्षद पति हाजी ओकास अंसारी के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की दसवीं पुण्य तिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। लोगों ने मिसाइल मैन कलाम साहब को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवम मुख्य वक्ता साहित्य कार डॉक्टर जयशंकर जय जी शामिल हुये।

इस मौके पर उन्होंने कहा की कलाम साहब आधुनिक भारत के कुशल शिल्पी थे। उन्होंने जीवन की अंतिम सांस तक देश की सेवा की। वह सच्चे राष्ट्र रन थे। उनका इरादा

फौलादी था और कार्य इंकलाबी रहा ।

कार्यक्रम का संचालन हाजी ओकास अंसारी ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा की कलाम साहब का पूरा जीवन त्याग बलिदान का प्रतीक था। वह भारत के दूरदृष्टा थे। और उन्होंने भारत को पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया और उन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया। इस मौके पर मुख्य रूप से शामिल मोहम्मद महतो अशफाक अहमद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घनश्याम जैनुल आबेदीन ने अपने विचार व्यक्त किया। और रमजान भाई सफरूउद्दीन शहाबुद्दीन सरदार अशफाक सलाउद्दीन रमजान भाई सहित कई लोग उपस्थित रहे।

हाजी ओकाश अंसारी पूर्व पार्षद वर्तमान पार्षद पति सरैया वाराणसी।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संविदा कर्मचारी नगरीय परिवहन सेवाएं उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जो आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे है उनका एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलकर एक पत्रक सौंपे

(जीएनएस)। 28 जुलाई को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संविदा कर्मचारी नगरीय परिवहन सेवाएं उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जो आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे है उनका एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलकर एक पत्रक सौंपे। पत्रक के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अवगत कराते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया की 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासन काल में जनहित में 130 बसों का बेड़ा वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट को संचालन हेतु दिया गया था जिसमें करीब 500 कर्मचारियों को रोजगार का अवसर मिला था। परन्तु 15 वर्ष का रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के पश्चात बसों को रोक दिया गया और इसी कार्यकाल में इलेक्ट्रॉनिक बसों को लाया गया जिसका संचालन प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है ऐसे में 500 कर्मचारियों का रोजगार भाजपा की मोदी सरकार ने छीन लिया गया। आज 500 कर्मचारी बेरोजगारी का दंश झेल रहे है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए अजय राय के माध्यम से इस प्रकरण पर आवाज उठाने हेतु निवेदन किया। पीड़ित कर्मचारियों से मिलने के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा की आज मेरे पास संविदा पर कार्यरत रहे

नगरीय परिवहन कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अपनी पीड़ा लेकर आए उनकी आँखों में आंसू थे और दिल में गहरी पीड़ा क्योंकि जिन लोगों ने वर्षों तक वाराणसी और अन्य शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सस्ती सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा दी आज वे बेरोजगारी की आग में झुलस रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक विभाग की बात नहीं है यह सैकड़ों परिवारों की आजीविका और सम्मान का प्रश्न है। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा जनहित में जिस वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा के माध्यम से 130 बसों के माध्यम से लगभग 500 लोगों को सीधा रोजगार मिला था। यह योजना सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं थी बल्कि यह शहरी भारत की नई सोच का प्रतीक थी जनता के लिए जनता के द्वारा। लेकिन आज मोदी सरकार की अदूरदर्शी नीतियों और निजीकरण की भूख ने इस जनकल्याणकारी योजना को समाप्त कर दिया। पिछले 15 वर्षों में न तो बसों का नवीनीकरण हुआ न ही कर्मचारियों की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। और जब रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हुई। तो उन्हें बिना किसी वैकल्पिक योजना के सड़क पर छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर नई इलेक्ट्रिक बसों को प्राइवेट कंपनियों को सौंप कर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया गया। यह निर्णय सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है यह सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं की भी अवहेलना है। कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि हम हर उस मेहनतकश कर्मचारी के साथ हैं जिसकी रोजी रोटी को इस सरकार ने छीनने का काम किया है। हम कांग्रेसजन इस मुद्दे को व्यापक रूप से उठाएंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा जिसमें इन कर्मचारियों की बहाली स्थायीकरण और आर्थिक सहायता की माँग की जाएगी।यह सिर्फ बेरोजगारी का मामला नहीं है

यह न्याय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का सवाल है। हम सभी संविदा कर्मचारियों को आश्वस्त करते हूँ कि कांग्रेस पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से उनके संघर्ष में साथ हैं और हर संभव कानूनी सामाजिक और राजनीतिक सहायता दिलवाने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में पीड़ित कर्मचारियों का समूह उपस्तिथि रहा है।

महर्षि साहूजी महाराज के अलख आरक्षण दिवस पर सैकडों बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरण किया गया।

(जीएनएस)। वाराणसी अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के द्वारा मुदार्हा कार्यालय पर आरक्षण की अलख जगाने वाले महर्षि साहूजी महाराज व बाबा साहब को नमन किया गया।

आरक्षण दिवस पर बच्चों को बैग कॉपी पेंसिल रबर कटर का वितरण किया गया।

मुख्य अतिथि नेशनल इक्वल पार्टी अध्यक्ष शशिप्रताप सिंह ने कहा कि आरक्षण की आवश्यकता है।

महर्षि शाहूजी महाराज बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी ज्योतिबा फुले सावित्री फुले ने शिक्षा और कमजोर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिये आरक्षण का प्रावधान की पेशकश किया।

शिक्षण सामग्री प्राप्त करने वालो में शिवा तमन्ना कुमारी आर्यन अंकित कुमार लक्की कुमारी दुर्गा कुमार अंकित कुमार पटेल रेशमी पवन कुमार

शशिप्रताप सिंह ने आगे कहा कि जिसको आज पाटीर्या राजनीतिकरण कर कमजोर कर रही है।

एक तरफ महापुरुषों ने काम जोड़ो कामेरवादी कमेरा समाज को आगे बढ़ाने के लिये प्रेरणा दिया वही दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर को बंद किया जा रहा है। शशिप्रताप सिंह ने सरकार से मांग किया कि जिन गांवों से स्कूल को दूर किया जा रहा उन गांवों को निःशुल्क बस की व्यवस्था की जाये।

अजय आर्या अध्यक्ष अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन की ओर से सैकड़ो बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरण किया गया।

मुख्य रूप दिनेश यादव गायन दिनेश पटेल ज्ञानदर्शन सूबेदार बागी योगेंद्र कुमार जैस्वारा गणेश राज मनोज माही सुनील कुमार बौद्ध धर्मेंद्र कुमार संदीप कुमार भास्कर चंदन कुमार आदि लोग उपस्थित थे।

जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वितीय वार्षिक चुनाव के नवनिर्वाचित पदाधिकारीयो का हुआ सम्मान

शुक्लागंज उन्नाव जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के द्वितीय वार्षिक चुनाव में विजयी हुवे प्रत्याशियों का आज गंगाघाट के शक्ति नगर पोनी रोड में समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता राजन कनौजिया द्वारा सम्मान किया गया सम्मान समारोह में पहुंचे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सूरज मिश्रा, उपाध्यक्ष राहुल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्षितिज बाजपेई, जिला कार्यकारिणी सदस्य इमरान खान, रेहान खान, प्रेम प्रकाश द्विवेदी, दिवाकर मिश्रा को राजन कनौजिया व उनके साथ उनके साथी सर्वेश कुमार, काशिफ खान, बेबी श्रीवास्तव ,अजय, सोना रावत ,गोपी , नाटे मुस्ताक ,व लड्डू द्वारा पुष्पमाला पहनकर स्वागत

सम्मान किया गया और सभी समाजसेवियों द्वारा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब संगठन द्वारा गरीबों की आवाज उठाने और मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिस पर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष सूरज मिश्रा द्वारा गरीब और न्याय से परेशान लोगों की मदद के लिए जल्द ही उचित व्यवस्थाएं करने का आश्वासन दिया गया।